

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर
(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई०ए०एस० अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :- 01/2017/भीलवाड़ा (2017/00013)

1. मैसर्स जय श्री पशु आहार उद्योग जोधड़ास, तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये प्रोपराइटर मदनसिंह पुत्र उगमसिंह, जाति राजपूत, निवासी जोधड़ास, तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये मु० आम र तमपाल सिंह पुत्र मदनसिंह, जाति राजपूत, निवासी जोधड़ास, तह० व जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांत

बनाम

1. मैसर्स मानसी रिसोर्ट्स जोधड़ास जरिये प्रोपराइटर रामपाल पुत्र बालूराम, जाति ब्राह्मण, निवासी 1-एल-1 आर०सी० व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा ।

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा दिनांक 8.8.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 106/2016 .

उपस्थित:-

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांत ।
2. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1 .
3. श्री सुवालाल गुंजल, पैरोकार सरकार रेस्पोंडेंट संख्या 2.

निर्णय

दिनांक :- 23.7.2018

अपीलांत ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.8.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

- 1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में राज्य सरकार के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 एवं 128 राज० भू-राजस्व अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी लीज खाते की भूमि खसरा नंबर 311/1 कुल रकबा 3.10 बीघा स्थित है जिसके पड़ोसी खातेदार भूमि की

सीमा बंदी को लेकर आये दिन विवाद करते है इस कारण प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश प्रदान किया जावे । अधी०न्याया० ने रेस्पों संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 8.8.2016 को स्वीकार कर विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये । अधी०न्याया० के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

- 2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेंट संख्या 1 के उपस्थित होने तथा अधी०न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट की बहस सुनी गई । xx
- 3- अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधी०न्याया० ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया एवं एकतरफा में निर्णय पारित किया है । अपीलाधीन आदेश से अपीलांत के हित व अधिकार प्रभावित होते है जिससे अपीलांत को अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.8.2016 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।
- 4- अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० पेश कर निवेदन किया कि अपीलांत अधी०न्याया० में पक्षकार नहीं था तथा ना ही अधी०न्याया० द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को किसी प्रकार का नोटिस ही जारी किया गया जिससे अपीलाधीन निर्णय की अपीलांत को जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.12.2016 को उस समय हुई जब रेस्पों संख्या 1 ने विवादित भूमि पर आकर अपीलांत को धमकी दी कि प्रकरण का निस्तारण रेस्पों के पक्ष में हो गया है और अब इस भूमि पर से प्रार्थी को बेदखल किया जावेगा । उक्त जानकारी के उपरांत अपीलांत ने अधी०न्याया० के निर्णय की पुष्टि कर निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 28.12.2016 को निर्णय की नकल मिलने पर अपीलांत ने रुपये-पैसे का इंतजाम कर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।
- 5- प्रकरण में गुणावगुण पर अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी०न्याया० ने अपीलांत को विधिवत् नोटिस दिये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है । अधी०न्याया० ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने आदेश क्रमांक 11403/7 दिनांक 8.5.1990 के द्वारा ग्राम जोधड़ास की आराजी खसरा

संख्या 311 मिन में से 1 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ अपीलांत मै0 जय श्री पशु आहार उद्योग के नाम से आवंटन की थी तत्पश्चात् अपीलांत ने उद्योग फर्म का पंजीयन करवा कर उक्त भूमि पर दो गोदाम का निर्माण करवा एवं 60 फीट गहरा कुआ खुदवाया, पानी के टैंक एवं टीन शेड लगवाये एवं बिजली का कनेक्शन करवाकर पशु आहार उद्योग संचालित करने हेतु मशीने लगवायी एवं मौके पर अपीलांत का उद्योग चालू है । विद्वान वकील अपीलांत ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित भूमि को अपीलांत को उद्योग प्रयोजन हेतु 4200/-रु0 जमा करवाने पर लीज पर दी गई किन्तु इसी भूमि में से रेस्प0 संख्या 1 को 16370/-रु0 प्रति बीघा की दर से भूमि का आवंटन किया गया जिसके विरुद्ध प्रार्थी/अपीलांत ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रीट याचिका संख्या 5368/2010 प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 4.6.2010 को अपीलांत के हक में प्रदान किया गया किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त निर्णय को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया है । रेस्प0 संख्या 1 पत्थरगढ़ी की आड़ में अपीलांत की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 8.8.2016 अपास्त यिका जावे । xx

- 6- विद्वान वकील रेस्प0डेटस संख्या 1 ने सर्वप्रथम अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 के जवाब में बहस एवं लिखित जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि खसरा नंबर 311 में से 1 बीघा भूमि का आवंटन होने का कथन अपीलांत ने किया है जो स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह भूमि जमाबंदी संवत् 2069 में राजकीय भूमि दर्ज है । अपीलांत दस्तावेजी साक्ष्यों से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । अपीलांत विवादित भूमि का खातेदार नहीं होने से अधी0न्याया0 में पक्षकार कायम नहीं किया गया था । अपीलांत पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 अस्वीकार किया जावे ।
- 7- विद्वान वकील रेस्प0 ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधी0 के संबंध में जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांत मियाद प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे संतोषप्रद एवं उचित नहीं है । अतः अपील अपीलांत मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है ।
- 8- प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील रेस्प0 संख्या 1 ने जवाब एवं लिखित बहस में कथन किया कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम जोधड़ास तहसील भीलवाड़ा स्थित आराजी खसरा नंबर 311 रकबा 8.07 बीघा, खसरा नंबर 311/2 रकबा 0.13, खसरा नंबर 31/3 रकबा 0.04 व खसरा नंबर 311/4 रकबा 0.03 बीघा औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा उक्त आराजी खसरा नंबर 311/4 रकबा 3.10 बीघा रेस्प0 संख्या 1 मैसर्स मानसी रिसोर्ट जोधड़ास के नाम दर्ज रिकार्ड है । विवादित भूमि खसरा नंबर 311/1 का रेस्प0 संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार दर्ज है जिसे अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का पूरा अधिकार है । विद्वान वकील

रेस्प0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट ने जिस खसरा नंबर 311 मिन में से 1 बीघा भूमि अपने नाम आवंटित होना बताया है उक्त आवंटन दिनांक 8.5.1990 को शर्त हुआ था जिसमें शर्त संख्या 4 व 5 के अनुसार आवंटी को तीन माह के भीतर समस्त वांछित कार्यवाही कर कब्जा प्राप्त करके लीजडीड संपादित करानी थी किन्तु अपीलांट/आवंटी द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं किये जाने से तथा उक्त आराजी की प्रीमीयम राशि जमा नहीं कराने के कारण उक्त आवंटन आदेश की शर्तों की पालना के अभाव में आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाने से उस आराजी पर अतिक्रमण मानते हुए तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा अपीलांट को दिनांक 8.6.2010 को बेदखल कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है । विवादित भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने से अपीलांट किस प्रकार व्यथित है दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट नहीं किया है । विद्वान वकील रेस्प0 ने बहस में आगे कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रश्न है उक्त आदेश प्रार्थी को एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.8.2016 को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है क्योंकि अपीलांट की रिट याचिका में पारित अंतरिम आदेश में केवल मात्र उसकी आराजी बाबत मार्केट वेल्यू निर्धारण हेतु जिलाधीश, भीलवाड़ा को निर्देशित किया गया है । वर्तमान में अपीलांट का आवंटन अस्तित्व में ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर उद्योग चालू होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे ।

- 9- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलेखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्प0 संख्या 1 से 3 की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते हैं । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण पत्थरगढ़ी से संबंधित है । अपीलांट का कथन रहा है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 311 मिन में से 1 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ अपीलांट मैसर्स जय श्री पशु आहार के नाम से आवंटन की गई थी जिस पर अपीलांट ने दो गोदम एवं 60 फीट गहरे कुएं का निर्माण करवा रखा है एवं पानी का टैंक व शेड आदि लगवाकर बिजली का कनेक्शन ले रखा है । रेस्प0 संख्या 1 पत्थरगढ़ी की आड़ में अपीलांट की भूमि पर कब्जा करना चाहता है । पत्थरगढ़ी/सीमाज्ञान के आदेश पारित करने से पूर्व पड़ोसी काश्तकारों को सुना जाना चाहिये किन्तु अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट जो कि विवादित भूमि खसरा नंबर 311 में 1 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन होने का कथन कर रहा है, को पक्षकार कायम किये बिना तथा बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे अपीलांट के हित प्रभावित होना प्रथमदृष्टया प्रकट होते हैं । न्यायहित में हम अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित समझते हैं । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.8.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 106/2016 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

- 10- चूंकि अपीलांत अधी०न्याया० के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं थे जिससे उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रारंभ से होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांत ने विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित किये हैं वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
- 11- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो० संख्या 1 ने अधी०न्याया० के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू-राजस्व अधी० 1956 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम जोधड़ास तह० जिला भीलवाडा में उसके खाते की भूमि आराजी नंबर 311/1 कुल किता 1 रकबा 3-10-00 बीघा बाबत् पत्थरगढ़ी का निवेदन किया था । इसके विपरीत अपीलांत का कथन है कि खसरा नंबर 311 मिन में से 1 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ अपीलांत को मैसर्स जय श्री पशु आहार उद्योग के लिये आवंटन हुआ था जिस पर अपीलांत ने दो गोदाम का निर्माण करा रखा है एवं 60 फीट गहरा कुंआ खुदवाकर पानी के टैंक व तीन शेड का निर्माण करवाकर बिजली का कनेक्शन ले रखा है जिस पर अपीलांत का कब्जा होकर उद्योग चालू है । रेस्पो० संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांत द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से अपीलांत का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया तथा तहसीलदार द्वारा अपीलांत को विवादित भूमि से बेदखल कर विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज किया जा चुका है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 311 व 311/1 रकबा क्रमशः 10 बीघा व 4 बीघा 10 बिस्वा का है । विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार, भीलवाडा ने अपने पत्र क्रमांक 756 दिनांक 5. 7.2008 से अवगत कराया था कि खसरा नंबर 311 रकबा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 311/1 रकबा 12 बिस्वा पर मदनसिंह काबिज है । मौके पर दो कमरे, पक्के कमरों के आगे बरामदा व एक रसोई बना रखी है । रेस्पो० संख्या 1 को खसरा संख्या 311/1 में से रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन हुआ है तथा अपीलांत को 1 बीघा का आवंटन हुआ है । रेस्पो० संख्या 1 ने अपीलांत के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त होने का कथन करते हुए भूमि सिवायचक होने का कथन किया है परन्तु इस कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य वगैरह प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा ना ही अपीलांत द्वारा उक्त कथन का खण्डन किया गया है जो एक जांच का विषय है । अधी०न्याया० को खसरा नंबर 311/1 संपूर्ण रकबे पर काबिज पड़ौसी काश्तकारों एवं उसके खसरा नंबर 311/1 से लगते हुए अन्य खसरा नंबरान के पड़ौसी काश्तकारों को प्रकरण में पक्षकार कायम कर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढ़ी के आदेश पारित करने चाहिये थे किन्तु अधी०न्याया० ने पड़ौसी काश्तकारों को प्रकरण में पक्षकार

कायम किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है ।

- 12- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 8.8.2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 01/2017 (2017/00013) बउनवानी मै0 जय श्री पशु आहार बनाम मै0 मानसी रिसोर्ट्स को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 106/2016 बउनवान मैसर्स मानसी रिसोर्ट्स बनाम तहसीलदार, भीलवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 8.8.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि खसरा संख्या 311/1 के समस्त काबिज पक्षकारान एवं खसरा संख्या 311/1 से लगते हुए अन्य खसरा नंबरान के पड़ौसी काश्तकारों तथा अपीलांत को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करे प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 23.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर